सर्वोच्चय न्यायालय की आख्या

पन्ना लाल और अन्य इत्यादि

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य

1 अगस्त, 1975

[ए. एन. राय, सी. जे., एम. एच. बेग और वाई. वी. चंद्रचूड, न्यायमूर्तिगण]

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, धारा 24, 28, 29 और 30 और राजस्थान आबकारी नियम, 1956 नियम 67 क , 67 झ, 67 ञ, 67 ट और 67 ठ- गारंटी और अनन्य विशेषाधिकारों के तहत देशी शराब की बिक्री के लिए आबकारी अनुज्ञप्ति- ठेकेदारों की निर्धारित राशि का भुगतान करने में विफलता- अपूर्ण गारंटी राशि की वसूली, यदि उगाही और उत्पाद शुल्क की वसूली के बराबर है।

देशी शराब की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत दिए गए थे। 1962-63 और 1963-64 के वर्षों के लिए देशी शराब की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति एक गारंटी प्रणाली के तहत ठेकेदारों को दिए गए थे। कुल गारंटीकृत राशि थी। जहां ठेकेदार गारंटीकृत राशि को पूरा करने में विफल रहे और कमी हुई, वहां कुल कमी के लिए मांग नोटिस जारी किए गए। 6 मार्च, 1964 से पहले कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता था। 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के वर्षों के लिए शराब ठेकेदारों ने अनन्य विशेषाधिकार प्रणाली के तहत अनुज्ञप्ति शुल्क की एक निर्दिष्ट राशि पर देशी शराब की बिक्री के लिए

अनुज्ञप्ति प्राप्त किए। जहां ठेकेदार गारंटीकृत राशि का भुगतान करने में विफल रहे, वहां कमी की मांग थी। अपीलार्थी, जो शराब के ठेकेदार थे, उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के माध्यम से गारंटीकृत राशि में कमी की मांग को चुनौती दी। उनका तर्क था कि कमी के रूप में जो मांग की जा रही थी, वह उत्पाद शुल्क लगाने के बराबर था। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि उस शराब ठेकेदारों से जो प्राप्त किया जा रहा था, वह देशी शराब बेचने के विशेष विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति में गारंटीकृत राशि थी। राज्य ने आगे तर्क दिया कि वर्ष 1967-68 के लिए और उसके बाद कमी के रूप में जो मांग की जा रही थी, वह निर्धारित गारंटीकृत राशि थी जो आबकारी राजस्व था। उच्च न्यायालय ने राज्य की दलीलों को स्वीकार कर लिया और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर प्राथमिकता दी गई है।

अपीलार्थियों के लिए यह तर्क दिया गया थाः (i) अनुज्ञप्ति में निर्गम मूल्य पात्र की कीमत से अलग हैं, लेकिन सरकारी अधिसूचना के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क सहित हैं और इसलिए, गारंटीकृत राशि के प्रवर्तन का अर्थ उत्पाद शुल्क की प्राप्ति है; (ii) सरकारी गोदाम से शराब की न्यूनतम मात्रा खरीदकर सरकार को आय देने का वादा जो अधिनियम की धारा 30 के अर्थ के भीतर ऐसे विशेषाधिकार के अनुदान के विचार में कुछ धन के भुगतान के बराबर नहीं है; (iii) राशि वर्ष 1968 से शुरू की गई अनन्य विशेषाधिकार प्रणाली के साथ-साथ वर्ष 1968 से प्रचलित गारंटी प्रणाली के तहत अनुज्ञप्तिधारी से वसूल किए जाने के लिए मांगी गई राशि कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना उठाई गई शराब पर उत्पाद शुल्क की मांग है; (iv) वर्ष 1967 तक दिए गए लाइसेंसों से जुड़ी शर्तों में आने वाला 'निर्गम मूल्य' शब्द 'शराब की लागत मूल्य' और 'उस पर देय उत्पाद शुल्क' के लिए एक समग्र नाम था और इसलिए गारंटी प्रणाली के तहत अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा 'निर्गम मूल्य' का भुगतान करने

के लिए एक समझौता 'लागत मूल्य' और 'उत्पाद शुल्क' को अलग-अलग वस्तुओं के रूप में भुगतान करने के लिए एक समझौते के बराबर था, हालांकि इसे निर्गम मूल्य के रूप में वर्णित किया गया था; (v) गारंटी और अनन्य विशेषाधिकार दोनों प्रणालियों के तहत अनुज्ञप्ति में उत्पाद शुल्क के भुगतान और समायोजन के बारे में एक शब्द होता है और दोनों प्रणालियों के तहत 'उत्पाद शुल्क' एक अलग वस्तु है जिसे अनुज्ञप्ति की शर्तों के रूप में भुकतान करने की सहमति हुई है।

दलीलों को खारिज करना और अपीलों को खारिज करना (केवल 1974 की सिविल अपील संख्या 1433 और 1974 सिवल अपील संख्या 1871).

अभिनिर्धारित: (1) अधिनियम की धारा 24, 28, 29 और 30 के प्रावधान और 1956 के राजस्थान आबकारी नियमों के नियम 67-क, 67-झ , 67-द, 67-ट और 67-ठ, में यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा भुगतान किए जाने के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्कः कीमत या विचार या किराया है जो सरकार निर्धारित एकमुश्त भुगतान में अपने विशेषाधिकार के साथ भाग लेने के लिए अनुज्ञप्तिधारियों से शुल्क लेती है और व्यापार या व्यावसायिक लेनदेन की एक सामान्य घटना है।

नाशिरवार और अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और अन्य (1975) भाग 1, यस. सी. सी. 29, हरि शंकर बनाम इक्साइज़ एण्ड टैक्सैशन डेप्यूटी कमिशनर, ने 21 जनवरी, 1975 को 1969 की सिविल अपील संख्या 365, माधवन बनाम असिस्टन्ट इक्साइज़ कमिशनर, पालघाट और अन्य 1969 आई. अल. आर. 2 केरल 71, द सेंट्रल प्रोविन्सेस और मोटर बेरार

सेल्स ऑफ मोटर स्प्रिट एण्ड लूब्रकन्ट टैक्सैशन ऐक्ट, 1938, (4) मोटर स्पिरिट और स्नेहक कराधान अधिनियम, 1938 का केंद्रीय प्रवीण और बरार बिक्री, मामला, [1939] अफ.सी.आर. 18 में रिपोर्ट किया गया, मैसर्स. गुरुस्वामी एंड कंपनी आदि बनाम स्टेट ऑफ मैसूर अन्य की स्थिति। [1967] 1 यस.सी.आर. 548, स्टेट ऑफ उड़ीसा और अन्य बनाम हरिनारायण जयस्वाल और अन्य [1972] 3 यस.सी.आर. 784 और कवरजी बी. भरुचा बनाम द इक्साइज़ कमिशनर और चीफ इक्साइज़ कमिशनर, अजमेर और अन्य [1954] यस.सी.आर. 873, संदर्भित।

(2) वर्तमान मामले में अनुज्ञप्ति पक्षों के बीच अनुबंध हैं। अनुज्ञप्तिधारियों ने स्वेच्छा से अनुबंध स्वीकार किए। उन्होंने दूसरों को बाहर करने के लिए अपने लाभ के लिए अनुबंधों का पूरा फायदा उठाया। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि यह अपीलार्थीयों के लिए करार से समझाने के लिए स्वतंत्र नहीं था कि भुगतान की अवधि कठिन थी।

(3) अनुज्ञप्ति में उल्लिखित गारंटीकृत राशि या निर्धारित राशि के भुगतान को लागू करने में उत्पाद शुल्क का कोई उद्ग्रहण नहीं है। क्योंकि, (i) अनुज्ञप्ति जहां अपीलार्थियों को प्रस्ताव और स्वीकृति के बाद या उनकी निविदाओं या नीलामी बोली को स्वीकार करके दिए गए हैं। अपीलार्थियों ने देशी शराब बेचने के विशेष विशेषाधिकार के लिए कीमत के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया। यदि वे भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं, जिसे वे अधिकार के बराबर मानते हैं; (ii) उत्पाद शुल्क का दायित्व डिस्टिलरी पर है और शराब ठेकेदारों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। 1965 से पहले कोई उत्पाद शुल्क नहीं था। उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बाद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है क्योंकि विक्रय का विशेषाधिकार नीलामी द्वारा या माल के अस्तित्व में आने से पहले प्रस्ताव और स्वीकृति

द्वारा प्रदान किया जाता है; और (iii) अपीलार्थियों द्वारा देय निर्धारित राशियों का संबंध केवल उस राशि से है जो वे उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त शराब की दुकानों से देशी शराब की बिक्री द्वारा वसूल कर सकते हैं। देशी शराब की कई किस्में हैं और इन किस्मों पर उत्पाद शुल्क की दरें अलग-अलग हैं। अपीलार्थी कोई विशेष मात्रा या किसी किस्म की कोई विशेष गुणवत्ता लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। किसी भी मात्रा या गुणवत्ता के संदर्भ के बिना, उत्पाद शुल्क के कथित उगाही का अनुमान लगाना असंभव है।

(4) समझौते के तहत निर्धारित एकमुश्त राशि को निर्गम मूल्य के बराबर नहीं किया जाना है। निर्गम मूल्य तभी देय होता है जब ठेकेदार देशी शराब के निर्दिष्ट मूल्य की विशिष्ट मात्रा की डिलीवरी लेते हैं। निर्गम मूल्य केवल ठेकेदारों द्वारा तैयार की गई शराब से संबंधित है और अप्रचलित शराब से संबंधित नहीं है। अप्रचलित शराब पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है और न ही उसे वसूला जा सकता है। निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर देशी शराब को शराब ठेकेदारों को बेचा जाता है। जहां तक शराब ठेकेदारों का संबंध है, वे शराब की कीमत का भुगतान करते हैं, भले ही कीमत में इसके घटक शामिल हो सकते हैं उत्पाद शुल्क जिसके संबंध में उनका कोई प्रत्यक्ष दायित्व नहीं है।

(5) वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने अनुज्ञप्तिधारी पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया है। इसके विपरीत, अनुज्ञप्ति केवल ठेकेदारों को रियायत माफी देने के उद्देश्य से निर्गम मूल्य के उत्पाद शुल्क घटक को ध्यान में रखता है। छूट की योजना यह है कि यदि शराब ठेकेदार उस मूल्य की शराब खरीदता है, जिसका उत्पाद शुल्क अनन्य विशेषाधिकार की कीमत के बराबर होता है, तो शराब ठेकेदारों को उसके लिए ऋण दिया जाएगा। समायोजन का प्रश्न केवल तब होता है जब शराब तैयार की जाती है, अन्यथा छूट का सूत्र तस्वीर में

बिल्कुल नहीं आता है। संक्षेप में, शराब ठेकेदार से जो वसूल करने की मांग की गई है, वह शराब ठेकेदार की ओर से अनुज्ञप्ति की शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण कमी का सवाल है।

बिमल चंद्र बनर्जी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, [1971] 1 यस.सी.आर. 844, संदर्भित।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: 1974 की सिविल अपील संख्या 1213-1220,1353,1354,1385-1386,1387-1388,1564,1566-1567,1579-1581,1608,1621. 1623-1624,1626,1630,1647,1764,1862,1432,1433 और 1871.

राजस्थान उच्च न्यायालय के मई 1974 के 9 वें दिन के निर्णय और आदेश रिट याचिका नं. 1497-1503 और 1505/1971 से।

अपीलार्थियों के लिए *के. सेन और बी. डी. शर्मा* (सिवल अपील संख्याओं 1213-1220 और 1862 मे).

अपीलार्थियों के लिए *बी. डी. शर्मा*, (सिवल अपील संख्याओं 1353, 1354 और 1647 में)

अपीलार्थियों के लिए *बद्री दास शर्मा और एस. आर. श्रीवास्तव*, (सिवल अपील संख्याओं 1623, 1432, 1433 और 1871 में).

अपीलार्थियों की ओर से *डी. वी. पटेल और एस. एस. खांडुजा* (सिवल अपील संख्या 1385 में).

अपीलार्थियों के लिए *एस. एस. खंडुजा,* (सिवल अपील संख्याओं 1386-1388,1530,1564,1566,1567,1579,1580,1581,1606,1622,1624, · 1626,1630 और 1764 में)

उत्तरदाताओं के लिए *एल. एम. सिंघवी और एस. एम. जैन* (सभी अपीलों में).

अदालत का निर्णय दिया गया था द्वारा **राय, मुख्य न्यायमूर्ति:-**

निर्णय द्वारा ये अपीलें प्रश्न को चालू करती हैं। क्या अपीलार्थियों को दिए गए उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति ने उन्हें अनुज्ञप्ति में उल्लिखित निर्धारित एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया है।

ये अपीलें देशी शराब अनुज्ञप्ति से संबंधित हैं।(a) 1962-63 और 1963-64 वर्षों के लिए (b) 1967-68 वर्षों के लिए और (c) 1968-69,1969-70 और 1970-71 वर्षों के लिए।

वर्ष 1962-63 और 1963-64 के लिए देशी शराब की बिक्री के लिए गारंटीकृत प्रणाली के तहत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति दिए गए। कुल गारंटीकृत राशि थी। जहां ठेकेदार गारंटीकृत राशि को पूरा करने में विफल रहे और कमी हुई, वहां कुल कमी के लिए मांग नोटिस जारी किए गए।

1967-68, 1968-69 और 1969-70 के वर्षों के लिए शराब ठेकेदारों ने अनन्य विशेषाधिकार प्रणाली के तहत अनुज्ञप्ति शुल्क की निर्धारित राशि पर देशी शराब की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किए। जहां ठेकेदार गारंटीकृत राशि का भुगतान करने में विफल रहे, वहां कमी की मांग थी।

अपीलकर्ता जो शराब के ठेकेदार थे, उन्होंने गारंटीकृत राशि में कमी की मांग को चुनौती दी। शराब के ठेकेदारों ने तर्क दिया कि कमी के रूप में जो मांग की जा रही थी, वह उत्पाद शुल्क लगाने के बराबर है। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि शराब ठेकेदारों से जो प्राप्त किया जा रहा था, वह देशी शराब बेचने के विशेष विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति में गारंटीकृत राशि थी। यहां यह कहा जा सकता है कि 6 मार्च, 1964 से पहले कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता था। उत्पाद शुल्क लागू होने के बाद वर्ष 1967-68 के दौरान और उसके बाद विशेष विशेषाधिकार प्रणाली के तहत गारंटीकृत राशि के लिए अनुज्ञप्ति जारी किए गए। राज्य ने तर्क दिया कि कमी के रूप में जो मांग की जा रही थी वह निर्धारित गारंटीकृत राशि थी जो उत्पाद शुल्क राजस्व थी।

वर्ष 1967-68 तक दिए गए लाइसेंसों में निम्नलिखित प्रमुख शर्तें थीं:-

(1) अनुज्ञप्तिधारी राजस्थान के राज्यपाल को यह गारंटी देता है कि वह .....मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में सरकार से ऐसी मात्रा में शराब प्राप्त करेगा और बेचेगा जिसका निर्गम..... मूल्य रुपये से कम नहीं होगा। (इसके बाद गारंटीकृत मूल्य के रूप में जाना जाता है जो..... मार्च.... पर प्रचलित है।

(2) शराब की आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी को प्रचलित निर्गम मूल्य पर की जाएगी, लेकिन ऐसे निर्गम मूल्य और 31 मार्च को प्रचलित दर पर गणना किए गए निर्गम मूल्य के बीच का अंतर गारंटी राशि में शामिल नहीं किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी को कमी का भुगतान करना होगा। 31 मार्च के निर्गम मूल्य पर किसी महीने के अंत तक उसके द्वारा प्राप्त शराब की कीमत..... और गारंटी की राशि, जो अगले महीने के दसवें दिन तक गोदाम में ग्यारह से बीत चुकी और विभाजित हो चुकी है, के गुणन के बीच, यदि कोई हो।

(4) भुगतान न करने के मामले में, अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा और जब इस तरह से रद्द कर दिया जाता है, तो उपर्युक्त अंतर को प्रतिभूति, नकद जमा से वसूल किया जाएगा और प्रतिभूति, यदि कोई हो, तो अनुज्ञप्तिधारी और जमानत से संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से वसूल किया जाएगा।

1968-69 से अनुज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख शर्तें निहित थीः-

(1) अनुज्ञप्तिधारक को रुपये जमा करने होंगे.. ...जिसे राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित विशेष विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति फीस के रूप में ली लाएगी। इससे उत्पाद शुल्क की राशि को विशेष विशेषाधिकार के लिए राशि के भुगतान के लिए समायोजित किया जाएगा, लेकिन यह समायोजन विशेष विशेषाधिकार के लिए राशि के भुगतान तक सीमित होगा। अनुज्ञप्तिधारक को उपर्युक्त राशि को 12 समान किश्तों में जमा करना होगा

और अगले महीने की 10 तारीख तक मासिक किश्तों को सरकारी कोषागार में जमा करना होगा। उस महीने में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निर्गम मूल्य के घटक के रूप में जमा की गई फीस को अनुज्ञप्ति-शुल्क की किस्त के तहत उत्पाद शुल्क के रूप में माना जाएगा।

(2) यदि अनुज्ञप्ति-धारक निर्धारित अवधि के भीतर उपर्युक्त शर्त के अनुसार किसी भी दो महीने के लिए किस्त जमा नहीं करता है, तो अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को अनुज्ञप्ति-धारक की नकद प्रतिभूति या उसके मुचलके से उस किस्त की राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, उसे अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्ति रद्द करने का भी अधिकार होगा।

अपीलार्थियों ने उस तर्क को दोहराया जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि जब राज्य सरकार गारंटीकृत राशि को लागू करना चाहती है तो यह अनुज्ञप्ति द्वारा उत्पाद शुल्क की वसूली के बराबर है। अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि अनुज्ञप्ति में निर्गम मूल्य कंटेनर की कीमतों से अलग हैं, लेकिन इसमें सरकारी अधिसूचना के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क शामिल है और इसलिए, गारंटीकृत राशि को लागू करने का मतलब उत्पाद शुल्क की प्राप्ति है।

अपीलार्थियों का तर्क है कि अपीलार्थियों से वसूल की जाने वाली अधूरी गारंटी राशि अनन्य विशेषाधिकार के मूल्य के रूप में एकमुश्त भुगतान का संतुलन नहीं है क्योंकि सरकारी अनुज्ञप्ति मंजूरी गारंटी प्रणाली में कहा गया है कि "अनुज्ञप्तिधारी वर्ष ..... के संबंध मे गारंटी देगा कि इस वर्ष के दौरान अपनी दुकान से बेचे जाने के लिए जारी देशी शराब के

जारी मूल्य से सरकार की आय..... के संबंध में" इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा यह कहा गया था कि सरकारी गोदाम से शराब की न्यूनतम मात्रा खरीदकर सरकार को आय देने का वादा राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अर्थ के भीतर ऐसे विशेषाधिकार के अनुदान के विचार में धन राशि के भुगतान के बराबर नहीं था।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि वर्ष 1968 से शुरू की गई अनन्य विशेषाधिकार प्रणाली के साथ-साथ वर्ष 1968 से पहले प्रचलित गारंटी प्रणाली के तहत अनुज्ञप्तिधारी से वसूल की जाने वाली राशि नहीं है, जबकि बिना ली गई शराब पर उत्पाद शुल्क की मांग है। अपीलार्थियों द्वारा दिए गए कारण यह हैं कि 1968 में शुरू की गई अनुज्ञप्ति की अनन्य विशेषाधिकार प्रणाली के तहत राशि का भुगतान करने और देशी शराब की आपूर्ति के लिए निर्गम मूल्य के एक घटक के रूप में दिए गए उत्पाद शुल्क के लिए विशेष रूप से जमा करने पर सहमति व्यक्त की गई थी और अनन्य विशेषाधिकार की राशि में समायोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

अपीलकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया कि 'निर्गम मूल्य' शब्द 'शराब की लागत मूल्य' और 'उस पर देय उत्पाद शुल्क' के लिए एक समग्र नाम था और इसलिए, गारंटी प्रणाली के तहत 'निर्गम मूल्य' का भुगतान करने के लिए अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक समझौता 'लागत मूल्य' और 'उत्पाद शुल्क' का भुगतान करने के लिए एक समझौते के समान था, हालांकि इसे निर्गम मूल्य के रूप में वर्णित किया गया था।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि गारंटी और अनन्य विशेषाधिकार दोनों प्रणालियों के तहत अनुज्ञप्ति में उत्पाद शुल्क के भुगतान और समायोजन के बारे में एक शब्द होता है और दोनों प्रणालियों के तहत 'उत्पाद शुल्क' एक अलग वस्तु है जिसे अनुज्ञप्ति के संदर्भ में भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की जाती है।

ये अनुज्ञप्ति राजस्थान आबकारी विभाग के तहत दिए गए थे। "1950 (अधिनियम के रूप संदर्भित) .....अधिनियम की धारा. 24 आबकारी आयुक्त को किसी भी व्यक्ति को अनन्य विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है।

(1) थोक द्वारा या दोनों के निर्माण या आपूर्ति का, या (2) थोक द्वारा या खुदरा द्वारा विक्रय का, या (3) थोक द्वारा या दोनों के निर्माण या आपूर्ति का, और खुदरा द्वारा विक्रय का,-राजस्थान राज्य के उन भागों के किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर, जहां तक अधिनियम का विस्तार है, कोई देशी शराब या मादक दवा।

अधिनियम की धारा 28 में यह प्रावधान है कि उत्पाद शुल्क या प्रतिपूरक शुल्क, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर या दरों पर, जो राज्य सरकार निर्देशित करेगी, आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, आयातित या निर्यात की जाने वाली किसी वस्तु पर लगाया जा सकता है, या अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी अनुज्ञप्ति के तहत परिवहन या निर्मित, खेती या संग्रहित, या अधिनियम के तहत स्थापित या अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी डिस्टिलरी, पॉट-स्टिल या शराब की भठ्ठी में निर्मित किया जा सकता है। धारा 28 के स्पष्टीकरण में यह

उपबंध किया गया है, कि इस धारा के अधीन शुल्क विभिन्न दरों पर उन स्थानों के अनुसार अधिरोपित किया जा सकता है जहां से किसी उत्पाद शुल्क या मादक पदार्थ को उपभोग के लिए हटाया जाना है या ऐसी वस्तु की भिन्न शक्ति और गुणवत्ता के अनुसार लगाया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 29 में यह प्रावधान है कि समय, स्थान और समय को विनियमित करने वाले ऐसे नियमों के अधीन। भुगतान का तरीका, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, ऐसा शुल्क ऐसे एक या अधिक तरीकों से लगाया जा सकता है जो राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे।

अधिनियम की धारा 30 में यह उपबंध किया गया है कि अध्याय V, जिसमें धारा 28,29 और 30 सम्मिलित है, के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क के स्थान पर या उसके अतिरिक्त आबकारी आयुक्त धारा 24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदान पर विचार करते हुए राशि का संदाय स्वीकार कर सकेगा।

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 ने नियम 67 झ, 67 ञ, 67 ट और 67 ठ में अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रदान की हैं। नियम 67 झ यह उपबंध करता है कि अधिनियम की धारा 24 के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर देशी शराब की खुदरा बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति उत्पाद शुल्क के स्थान पर या उसके अतिरिक्त ऐसी एकमुश्त राशि के भुगतान की शर्त पर प्रदान की जा सकती है जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाए और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों

के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा निर्धारित की जाएं। नियम 67 ञ में यह उपबंध है कि नियम 67 ज ञ के उप-नियम 2 से 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बातचीत द्वारा आवंटन के रूप में नियम 67 झ के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किया जा सकता है। नियम 67 ट में यह प्रावधान है कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन, जिला आबकारी अधिकारी किसी भी क्षेत्र के लिए नीलामी के लिए नियम 67 झ के तहत अनुज्ञप्ति रख सकता है। ऐसी नीलामी में पीठासीन अधिकारी उत्पाद शुल्क के स्थान पर या उसके अतिरिक्त देय अनन्य विशेषाधिकार के लिए एकमुश्त भुगतान का आह्वान करेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। नियम 67 ठ में यह प्रावधान है कि आबकारी आयुक्त अपने विवेकाधिकार पर किसी तीसरे पक्ष के साथ बातचीत करके किसी भी क्षेत्र के लिए नियम 67 झ के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। एक प्रावधान है कि उच्चतम बोलीदाता या उच्चतम निविदाकार, यदि कोई हो, को उच्च प्रस्ताव देने का मौका दिया जाएगा, जब तक कि उसे अनुज्ञप्ति पाने से वंचित नहीं किया गया हो या उसने नियम 67(2) के तहत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया हो।

अपीलार्थियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क वह मूल्य या प्रतिफल या किराया है जो सरकार निर्धारित एकमुश्त भुगतान में अपने विशेषाधिकार के साथ भाग लेने के लिए अनुज्ञप्तिधारियों से लेती है और यह व्यापार या व्यावसायिक लेनदेन की एक सामान्य घटना है। यह न्यायालय *नाशिरवार और अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और अन्य (1)* में हाल के फैसले में है, और गैर-सूचित निर्णय में *हरिशंकर बनाम डेप्यूटी इक्साइज़ एण्ड टैक्सैशन कमिशनर (2)* ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य को राजस्व बढ़ाने के लिए शराब बनाने और बेचने और उक्त अधिकार को बेचने का अनन्य अधिकार है।

व्यापार की प्रकृति ऐसी है कि राज्य नीलामी या निजी संधि द्वारा खेती करके शराब बेचने का अधिकार प्रदान करता है। किराया शराब बनाने या बेचने के लिए सरकार द्वारा दिए गए विशेषाधिकार के लिए विचार है। किराया न तो कर है और न ही उत्पाद शुल्क। किराया सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए समझौते का प्रतिफल है।

वर्तमान मामले में अनुज्ञप्ति पक्षों के बीच अनुबंध हैं। अनुज्ञप्तिधारियों ने स्वेच्छा से अनुबंध स्वीकार किए। उन्होंने दूसरों को बाहर करने के लिए अपने लाभ के लिए अनुबंधों का पूरा फायदा उठाया। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि यह अपीलार्थियों के लिए इस आधार पर अनुबंधों से वापस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था कि भुगतान की शर्तें भारी थीं। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण थे कि अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने प्रतियोगियों को छोड़कर अनुज्ञप्ति स्वीकार कर लिया था और यह अनुज्ञप्तिधारियों के लिए शर्तों के असुविधाजनक परिणाम या शर्तों की कठोरता के आधार पर शर्तों को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा।

माधवन बनाम असिस्टन्ट इक्साइज़ कमिशनर, पालघाट और अन्य (3) में भी कानूनी स्थिति सही ढंग से बताई गई है। जहां यह कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए लिया गया किराया शराब बेचने के विशेषाधिकार के लिए विचार है 'वर्तमान अपील में अनुज्ञप्तिधारियों ने स्वेच्छा से शराब बेचने के अनन्य विशेषाधिकार के लिए निर्धारित एकमुश्त की गारंटीकृत राशि का भुगतान करने का अनुबंध किया है।

द सेंट्रल प्रोविन्सेस और मोटर बेरार सेल्स ऑफ मोटर स्प्रिट एण्ड लूब्रकन्ट टैक्सैशन ऐक्ट, 1938, (4) मामले में यह कहा गया है कि कई अधिनियमों में जिनके द्वारा उत्पाद शुल्क

अधिरोपित किया गया है, यह उपबंध किया गया है कि अयस्क उत्पादन के स्थान से सक्षम वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाता है और खुदरा बिक्री पर उत्पाद शुल्क अधिरोपित करने का कोई उपबंध नहीं है। कई अधिनियमों में निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा कुछ मामलों में एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है, जिसे या तो विशेषाधिकार के लिए या एकाधिकार के अस्थायी अनुदान के लिए विचार के रूप में भुगतान के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उत्पाद शुल्क या उनके जैसे कुछ भी नहीं हैं। (देखो 1939 आफ. सी.आर.18 पीपी 53 और 54 पर)

यह न्यायालय *मैसर्स. गुरुस्वामी एंड कंपनी आदि बनाम स्टेट ऑफ मैसूर और अन्य* (5) में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या किसी निर्दिष्ट दुकान में शराब की बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिए दुकान के किराए का भुगतान एक उत्पाद शुल्क है। *गुरुस्वामी* के मामले (ऊपर) में याचिकाकर्ताओं ने ताड़ी की दुकानों के एक समूह के लिए दुकान का किराया या 'किस्त' का भुगतान किया, जिसकी राशि 3,61,116 रुपये प्रति माह। यह 'किस्त' राशि अस्थिर ताड़ी की दुकानों के विशेष विशेषाधिकार की नीलामी बिक्री में निर्धारित की गई थी। अधिसूचना नीलामी ने कई प्रकार की उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर शुल्क, मूल्य आदि की दरों का उल्लेख किया है। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक निश्चित दर पर स्वास्थ्य उपकर, दुकान के किराए और ताड़ी पर वृक्ष कर और उत्पाद शुल्क के अन्य शुल्कों पर भी देय होगा। याचिकाकर्ताओं ने स्वास्थ्य उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए राज्य के अधिकार को चुनौती दी। इसका मुख्य आधार यह था कि स्वास्थ्य उपकर वास्तव में एक कर था, न कि केवल उपकर। इस न्यायालय ने कहा कि गुरुस्वामी के मामले (उपरोक्त) में उगाही का वास्तविक चरित्र या प्रकृति यह थी कि यह ताड़ी बेचने के विशेष विशेषाधिकार के लिए भुगतान था। भुगतान का ताड़ी के उत्पादन या निर्माण से कोई गहरा

संबंध नहीं था। उगाही का उत्पादन या निर्माण से एकमात्र संबंध यह था कि इसने अनुज्ञप्तिधारी को इसे बेचने में सक्षम बनाया। ताड़ी पर उत्पाद शुल्क का भुगतान वृक्ष कर के रूप में किया जाता है। जो ताड़ी रखता है वह वृक्ष कर देता है। ताड़ी बेचने के विशेषाधिकार की नीलामी माल के अस्तित्व में आने से बहुत पहले की गई थी। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य उपकर को उत्पाद शुल्क नहीं पाया गया। स्वास्थ्य उपकर के संबंध में कर योग्य घटना वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन नहीं था, बल्कि माल बेचने के लिए अनुज्ञप्ति की स्वीकृति थी।

स्टेट ऑफ उड़ीसा और अन्य बनाम हरिनारायण जयस्वाल और अन्य (1) में इस न्यायालय का एक न्यायपीठ निर्णय में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देशी शराब के निर्माण और बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के अनुदान पर विचार किया गया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकार को अनन्य विशेषाधिकार को इस तरह से बेचने की शक्ति दी गई है जो वह उचित समझती है, एक बहुत व्यापक शक्ति है। *कवरजी बी. भरुचा बनाम द इक्साइज़ कमिशनर और चीफ इक्साइज़ कमिशनर, अजमेर और अन्य* (2) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि थोक या खुदरा में शराब बेचने के अनन्य अधिकार को बेचने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है। आबकारी राजस्व राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनन्य विशेषाधिकार को बेचने की सरकार की शक्ति सार्वजनिक नीलामी या बातचीत द्वारा है। यह तथ्य कि देशी शराब की बिक्री से प्राप्त शत्रु मूल्य एक आबकारी राजस्व है, अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलता है। बिक्री राजस्व बढ़ाने का एक तरीका है।

इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्थापित होता है कि राज्य को भुगतान करने के लिए अपीलार्थियों द्वारा स्वेच्छा से सहमत की गई एकमुश्त राशि उत्पाद शुल्क के प्रभार नहीं हैं, बल्कि राज्य द्वारा अपीलार्थियों को दिए गए खुदरा बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिए लूटी हुई राशि या किराये या एकमुश्त राशि की प्रकृति की हैं।

इन कारणों से गारंटीकृत राशि या अनुज्ञप्ति में उल्लिखित निर्धारित एकमुश्त राशि के भुगतान को लागू करने में कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है। पहले अनुज्ञप्ति अपीलार्थियों को प्रस्ताव और स्वीकृति के बाद या उनकी निविदाओं या नीलामी बोली को स्वीकार करके दिए गए थे। अपीलार्थियों ने देशी शराब बेचने के विशेष विशेषाधिकार के लिए कीमत के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया। अपीलार्थी अधिकार के मूल्य के समतुल्य भुगतान करने के लिए सहमत हुए। दूसरा, निर्धारित भुगतान का देशी शराब के उत्पादन या निर्माण से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि यह अनुज्ञप्तिधारी को इसे बेचने में सक्षम बनाता है। देशी शराब का उत्पादन आसवन कारखानों द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 28 के तहत और प्रासंगिक शुल्क अधिसूचनाओं के तहत उत्पाद शुल्क निर्माण पर है न कि शराब की बिक्री या खुदरा बिक्री पर। शुल्क अधिसूचना के तहत शराब ठेकेदारों से कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है या एकत्र नहीं किया जाता है जो केवल शराब की कीमत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कर योग्य घटना ठेकेदारों को शराब की बिक्री नहीं है, बल्कि शराब का निर्माण है। शराब ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए जो भुगतान करते हैं, वह देशी शराब बेचने के लिए विशेष विशेषाधिकार के लिए भुगतान है। उत्पाद शुल्क का दायित्व डिस्टिलरी पर है और शराब ठेकेदारों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। 1965 से पहले कोई उत्पाद शुल्क नहीं था। अपीलार्थियों को गारंटीकृत राशि का भुगतान करना आवश्यक था। उत्पाद शुल्क लागू होने के बाद स्थिति में कोई

बदलाव नहीं किया जाता है क्योंकि बिक्री का विशेषाधिकार नीलामी द्वारा या माल के अस्तित्व में आने से पहले प्रस्ताव और स्वीकृति द्वारा दिया जाता है। आबकारी अनुबंधों का निपटान पिछले वर्ष में किया जाता है। तीसरा, अपीलार्थियों द्वारा देय निर्धारित राशियों का संबंध केवल उस राशि से है जो अपीलार्थियों को पहले से पता था कि वे उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त शराब की दुकानों से देशी शराब की बिक्री द्वारा वसूल कर सकते हैं। देशी शराब की कई किस्में हैं और इन किस्मों पर उत्पाद शुल्क की दरें अलग-अलग हैं। अपीलार्थी कोई विशेष मात्रा या किसी किस्म की कोई विशेष गुणवत्ता लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। किसी भी मात्रा या गुणवत्ता के संदर्भ के बिना, उत्पाद शुल्क के कथित उगाही का अनुमान लगाना असंभव है।

1965 में उत्पाद शुल्क लागू होने से पहले, निर्गम मूल्य में निर्गम मूल्य नियमों के तहत उत्पाद शुल्क का एक काल्पनिक घटक भी नहीं था। अतः अपीलार्थियों द्वारा देय संविदात्मक राशियों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। वर्ष 1965 के बाद प्रचलित गारंटी प्रणाली या अनन्य विशेषाधिकार प्रणाली के तहत लाइसेंसों में उत्पाद शुल्क के संदर्भ केवल समायोजन या रियायत के उद्देश्यों के लिए हैं। यह वर्तमान में अनुज्ञप्ति के वर्ष में लगाया गया या लगाया गया उत्पाद शुल्क नहीं है जो गैर-शराब के संबंध में एकत्र किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष में प्रचलित निर्गम मूल्य के संदर्भ में निर्गम मूल्य का समायोजन है। राजस्थान उत्पाद शुल्क नियम, 1966 के नियम 67-क में मूल्य को उस वित्तीय वर्ष से पहले 1 जनवरी को वर्तमान मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे गारंटी संबंधित है। नियम 67-क के तहत गारंटी प्रणाली के तहत देशी शराब की खुदरा दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति उन व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं जो सरकारी गोदाम से शराब लेने और एक वित्तीय वर्ष या उसके कुछ हिस्से में एक निर्दिष्ट मूल्य की देशी शराब, जिसे गारंटी की

राशि कहा जाता है, बेचने की गारंटी देते हैं। नियम 67-क 1 का स्पष्टीकरण है कि उस नियम के प्रयोजन के लिए मूल्य सरकारी गोदाम में कुल निर्गम मूल्य होगा जिसकी गणना उस वित्तीय वर्ष से पहले जनवरी के पहले दिन ऐसी वर्तमान कीमत की दर पर की जाती है जिससे गारंटी संबंधित है। गारंटी प्रणाली के तहत अनुज्ञप्ति या तो निविदाएं आमंत्रित करके या नीलामी द्वारा या बातचीत द्वारा दिए जाते थे। नियम 67-क के अधीन गारंटी की राशि होगी (क) जहां अनुज्ञप्ति देने के लिए स्वीकृत निविदा की राशि निविदा आमंत्रित करके अनुज्ञप्ति दिया जाता है; (ख) जहां अनुज्ञप्ति देने के लिए स्वीकृत बोली की राशि नीलामी द्वारा दी जाती है; और (ग) जहां अनुज्ञप्ति नीलामी या बातचीत द्वारा दिया जाता है, गारंटी की राशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकार की गई राशि होगी।

समझौते के तहत निर्धारित एकमुश्त राशि को निर्गम मूल्य के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। निर्गम मूल्य तभी देय होता है जब ठेकेदार देशी शराब के निर्दिष्ट मूल्य की एक विशेष मात्रा की डिलीवरी लेते हैं। निर्गम मूल्य केवल ठेकेदारों द्वारा तैयार की गई शराब से संबंधित है और अप्रचलित शराब से संबंधित नहीं है। अप्रचलित शराब पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है और न ही वसूला जा सकता है। निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर देशी शराब को शराब ठेकेदारों को बेचा जाता है। जहां तक शराब ठेकेदारों का संबंध है, वे शराब की कीमत का भुगतान करते हैं, भले ही कीमत में उत्पाद शुल्क का घटक शामिल हो, जिसके संबंध में उनका कोई प्रत्यक्ष दायित्व नहीं है। माचिस का डिब्बा या मोटर कार या रेफ्रिजरेटर खरीदने वाले व्यक्ति के मामले में चित्रण पाए जा सकते हैं। जब खरीदार माचिस के डिब्बे, या मोटर कार या रेफ्रिजरेटर की कीमत का भुगतान करता है तो कीमत में इन वस्तुओं के निर्माण पर लगाया गया और एकत्र किया गया उत्पाद शुल्क शामिल होता है।

वस्तुओं की कीमत में अनिवार्य रूप से अलग-अलग घटक शामिल होते हैं, लेकिन एक खरीदार द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत निर्माताओं द्वारा भुगतान या देय शुल्कों और करों से अलग होती है। लागत और करों के सभी घटकों का प्रभाव अनिवार्य रूप से उपभोक्ता पर पड़ता है। उपभोक्ता जो भुगतान करता है वह माल की कीमत है न कि पूर्ववर्ती घटकों की।

लाइसेंसों के तहत अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देय राशि की एक सहमत राशि निर्धारित करने के बाद लाइसेंसों में छूट की योजना प्रदान की जाती है। शराब ठेकेदार को उसके द्वारा भुगतान किए गए निर्गम मूल्य के उत्पाद शुल्क घटक की सीमा तक निर्धारित राशि का भुगतान करने के उसके दायित्व के मामले में छूट दी जाती है। इसलिए निर्गम मूल्य का उत्पाद शुल्क घटक केवल शराब ठेकेदार को दी जाने वाली रियायत या छूट की मात्रा या सीमा का माप है। रियायत वह नहीं है जो ठेकेदार द्वारा राज्य को भुगतान किया जाता है, बल्कि यह राज्य द्वारा ठेकेदार को दिए गए विशेष विशेषाधिकार के लिए निर्धारित राशि में छूट या कमी है। अनन्य विशेषाधिकार के लिए देय एकमुश्त राशि को निर्गम मूल्य के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। संक्षेप में, शराब ठेकेदारों से जो वसूल करने की मांग की गई है, वह शराब ठेकेदार की ओर से अनुज्ञप्ति की शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण हुई कमी है।

निर्धारित राशियों का भुगतान करने के लिए अपीलार्थियों का संविदात्मक दायित्व उनके द्वारा बेची गई शराब की मात्रा पर निर्भर करता है जो केवल अनुज्ञप्ति के तहत उनके द्वारा अर्जित की जाने वाली छूट के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। अनुज्ञप्ति के तहत शराब पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है। यह सुझाव देना कि अनुज्ञप्ति बाध्य करता है; ठेकेदारों को अप्रचलित शराब पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना

अनुज्ञप्ति की शर्तों को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ रहा है। उत्पाद शुल्क केवल देश की शराब की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में एकत्र किया जाता है। अप्रचलित शराब के संबंध में कोई उत्पाद शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

निर्गम मूल्य के एक विशिष्ट और मात्रात्मक भाग की सीमा तक अपीलार्थियों के संविदात्मक दायित्व में कमी के रूप में समायोजन विशुद्ध रूप से रियायत या छूट का एक उपाय है और गणना की एक विधि है। समायोजन का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब शराब तैयार की जाती है, अन्यथा छूट का सूत्र तस्वीर में बिल्कुल नहीं आता है।

अपीलार्थियों ने इस तर्क के समर्थन में *बिमल चंद्र बनर्जी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश* (1) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया कि राज्य की ओर से पूर्ण गारंटीकृत राशि या निर्धारित राशि को लागू करने का प्रयास से उत्पाद शुल्क एकत्र कर रहा है। बिमल चंद्र बनर्जी के मामले (उपर्युक्त) में राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना द्वारा और अनुज्ञप्ति की शर्तों में परिवर्तन करके अप्रचलित शराब पर उत्पाद शुल्क लगाया गया था। यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक ठेकेदार द्वारा शराब की निश्चित न्यूनतम मात्रा को अहरित करना होगा, जो घाटे के शुल्क से संबंधित महीनों के बाद प्रत्येक महीने की 10 तारीख को या उससे पहले कुल न्यूनतम शुल्क के घाटे के मासिक औसत को हर महीने पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। वहाँ निर्णय यह था कि विवादित अधिसूचना द्वारा अप्रकाशित शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने में, राज्य सरकार उन शक्तियों का प्रयोग कर रही थी जो उसके पास नहीं थीं। वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने अनुज्ञप्तिधारी पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया है। इसके विपरीत, अनुज्ञप्ति केवल ठेकेदारों को रियायत या छूट देने के उद्देश्यों के लिए निर्गम मूल्य के उत्पाद शुल्क घटक

को ध्यान में रखता है। बिमल चंद्र बनर्जी के मामले (ऊपर) में विवादित अधिसूचना पर इस आधार पर हमला किया गया था कि यह राज्य की विधायी क्षमता से अधिक थी। यहां ऐसा कोई सवाल नहीं है। वर्तमान मामले में छूट की योजना यह है कि यदि शराब ठेकेदार ने मूल्य की शराब खरीदी है, तो उत्पाद शुल्क जहां अनन्य विशेषाधिकार की कीमत के बराबर है, शराब ठेकेदारों को उसके लिए क्रेडिट दिया जाना है।

ये समझौते शराब ठेकेदारों को विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए निर्धारित राशि के लिए निर्धारित अवधि के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र में देशी शराब बेचने का विशेष विशेषाधिकार देते हैं। यदि ठेकेदार कोई शराब नहीं बेचते हैं तो वे अभी भी निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे शराब बेचते हैं तो उन्हें विशेष विशेषाधिकार की कीमत में छूट का लाभ दिया जाता है। इस छूट का उपाय उत्पाद शुल्क है जो इस हद तक लगाया जा सकता है कि शराब ठेकेदार उनके द्वारा देय उत्पाद शुल्क में विशेष विशेषाधिकार की पूरी राशि को बेअसर कर सकें। यदि ठेकेदार पर्याप्त मात्रा में शराब उठाने में विफल रहते हैं और इस तरह विशेष विशेषाधिकार की पूरी कीमत को बेअसर करने में विफल रहते हैं तो ठेकेदारों को उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाता है।

इन कारणों से अपीलार्थियों की दलीलें विफल हो जाती हैं। अपीलों को खारिज कर दिया जाता है सिवाय इसके कि 1974 की सिविल अपील सं. 1433 और 1974 की सिविल अपील सं. 1871 में पक्षकारों को अपनी लागतों का भुगतान और वहन स्वयं करना चाहिए जैसा कि उन्होंने उच्च न्यायालय में किया था।

1974 की सिविल अपील में संख्या 1433 वर्ष 1963-64 के संबंध में शराब की कम आपूर्ति है। वर्ष 1974 के सिविल अपील में नं. 1871 के संदर्भ में 1967-68 में शराब की आपूर्ति कम थी। इन दो वर्षों के लिए इन अपीलों में, आदेश 29 अगस्त, 1974 के सिविल अपील सं. 1974 के 1170, 1171 और 1176 में पारित आदेश के समान होगा, इस संशोधन के साथ कि यदि इन मामलों में कोई अंतरिम रोक लगी है, तो अंतरिम रोक हटा दी जाएगी।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

पन्ना लाल और अन्य इत्यादि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य

श्री चंद्रकान्त शुक्ला की देख-रेख मे अधिवक्ता मयंक कुमार सिंह द्वारा अनुवादित।